



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2003/27 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अभिसूचना

जिमला-171 004, 18 जुलाई, 2003

संख्या वि०स०-लैज-गवर्नमेंट बिल/1-78/2003.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) बिल, 2003 (2003

का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 18 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2003 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1994 का
13.

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

संक्षिप्त नाम
और
प्रारम्भ।

(2) यह 15 नवम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1994 का
13.

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 14 की उप-धारा (2) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 14
का
संशोधन।

“परन्तु यह और कि विद्यमान नगर पंचायत को उन्नत कर गठित की गई नगरपालिका परिषद् के सिवाय, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ के पश्चात् नगरपालिका का प्रथम निर्वाचन, उसके नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 268 में “तब तक के लिए नियुक्त कर सकती है, जब तक नगरपालिका स्थापित नहीं कर दी जाती” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या तब तक के लिए नियुक्त कर सकती है जब तक कि नगरपालिका स्थापित नहीं कर दी जाती, जो भी पूर्वतर हो” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 268
का
संशोधन।

2003 का 5.

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

निरसन और
व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगर निगम शिमला से कतिपय क्षेत्रों को निकालने के पश्चात् राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या यू0 डी0-ए (1)-3/2000-1, तारीख 4 फरवरी, 2002 द्वारा तीन नगर पंचायतों नामतः टुटू, न्यू शिमला (कमुस्पटी) और ढल्ली का सृजन किया। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् गठित की गई नगरपालिका का प्रथम निर्वाचन, इसके नगरपालिका (म्यूनिसिपैलिटी) के रूप में अधिसूचित होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित है। नव-गठित नगरपालिका के निर्वाचन के संचालन के लिए धारा 14 में यथा उपबन्धित, एक वर्ष की अवधि का 3 फरवरी, 2003 को अवसान होना था। आवश्यक अवसंरचना जैसा कि कमियाँ, कार्यालय भवनों, वजट इत्यादि की कमी के कारण, यह पाया गया कि 3 फरवरी, 2003 से पूर्व उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचन कराना सम्भव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगली विधान सभा का निर्वाचन भी फरवरी, 2003 में नियत था और इसलिए कर्मचारिवृन्द ने राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संचालन में रत रहना था। अतः नवगठित नगर पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के लिए विद्यमान एक वर्ष की अवधि के स्थान पर दो वर्ष की अधिकतम अवधि का उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया था। यह भी आवश्यक समझा गया कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुरूप धारा 268 में भी छः महीने की समय अवधि को बढ़ा कर दो वर्ष का प्रावधान कर दिया जाए।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2002 तारीख 12 नवम्बर, 2002 को राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था और उसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 15 नवम्बर, 2002 को प्रकाशित किया गया था, परन्तु उक्त अध्यादेश, विधान सभा के पिछले सत्र में, नियमित विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का 5) को 19 जून, 2003 को प्रख्यापित किया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 19 जून, 2003 को प्रकाशित किया गया। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य सत्री।

शिमला :

तारीख, 2003

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

* हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री।

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि)

शिमला :

....., 2003

Bill No. 7 of 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title
and comm-
encement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 15th day of November, 2002.

Amendment
of section
14.

2. In section 14 of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994, (hereinafter referred to as the 'Principal Act'), in sub-section (2) for the existing second proviso, the following shall be substituted, namely:—

13 of 1994.

“Provided further that the first election to a municipality after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Second Amendment) Act, 2003, except a municipal council constituted by upgrading an existing Nagar Panchayat, may be held within a period of two years of its being notified as a municipality.”

Amendment
of section
268.

3. In section 268 of the principal Act, for the words “six months”, the words “two years” shall be substituted.

Repeal and
saving.

4. (1) The Himachal Pradesh Municipal (Second Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

5 of 2003.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

After excluding certain areas from the Municipal Corporation Shimla, the State Government vide notification No. UD-A(1)-3/2000-I, dated 4th February, 2002 created three Nagar Panchayats namely, Nagar Panchayat Totu, New Shimla (Kasumpti) and Dhalli. First election to a municipality constituted after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 is required to be held within a period of one year of its being notified as a municipality. The period of one year provided in section 14 for conduct of election to a newly constituted municipality was to expire on 3rd February, 2003. Due to lack of essential infrastructure such as personnel, office building, budget etc., it was felt that the holding of elections to the said Nagar Panchayats before 3rd February, 2003 will not be possible. Besides, the elections to the next Legislative Assembly were also due in February, 2003 and as such, the staff was engaged for conduct of election to the State Legislative Assembly. Thus it was considered necessary to provide maximum period of two years for conduct of elections to the newly constituted municipalities against existing period of one year. It was also considered necessary to increase period of six months to maximum period of two years in section 268 so as to make provisions in consonance with section 14 of the Act *ibid*.

The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2002 was promulgated on 12th day of November, 2002 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 15th day of November, 2002, but the said Ordinance could not be replaced by a regular Bill in the last Vidhan Sabha Session.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal (Second Amendment) Ordinance, 2003 (Ordinance No. 5 of 2003) on the 19th day of June, 2003 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 19th day of June, 2003. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without any modification.

SHIMLA :

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Date

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2003

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The....., 2003